मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र से प्रकाशित

पत्रिका

सभी वर्गों के सहयोग से हमने वैक्सीन के 10 करोड़ डोज लगाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। वेंटीलेटर पर जाने से अच्छा वैक्सीन लगवाना है। मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना अब मर्जी की बात नहीं रही है। अब यह व्यक्ति की सामाजिक जिम्मेदारी है।
-शिवराज सिंह चौहान, सीएम

कितने महिला-पुरुष: 5,22,67,747 पुरुष | 4,78,86,110 महिलाएं

10,00,00,000 डोज लगाकर रचा कीर्तिमान

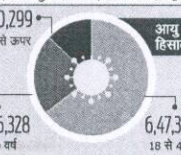

मध्यप्रदेश ने वैक्सीन के 10 करोड़ से ज्यादा डोज लगाकर कीर्तिमान रच दिया है। बुधवार को 10.91 लाख डोज के साथ आंकड़ा 10,01,75,614 पर पहुंच गया।

हमसे आगे ये राज्य

उत्तरप्रदेश	19,00,49,339
महाराष्ट्र	12,95,38,223
पश्चिम बंगाल	10,14,18,278

ओमिक्रॉन बेलगाम: कोविड-19 की तीसरी लहर की प्रबल आशंका

'डेल्मीक्रोन' से बढ़ी आर-नॉट वैल्यू

(डेल्टा + ओमिक्रॉन)

दिल्ली में क्रिसमस व नए साल के जश्न में जमावड़े पर रोक

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुंबई/नई दिल्ली. अमरीका और यूरोपीय देशों की तरह भारत में भी 'डेल्मीक्रोन लहर' की चर्चा होने लगी है। कोरोना के ओमिक्रॉन और डेल्टा वैरिएंट एक साथ सक्रिय होने को 'डेल्मीक्रोन लहर' कहा जा रहा है। भारत में दोनों सक्रिय हैं। ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद कई राज्यों में कोरोना वायरस की आर-नॉट वैल्यू बढ़ने लगी है। बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और नगालैंड में यह राष्ट्रीय औसत 0.89 से ऊपर पहुंच गई है।

आर-नॉट वैल्यू से यह पता चलता है कि वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति औसतन कितने स्वस्थ लोगों को बीमार कर रहा है। आर-नॉट वैल्यू 1 से कम होने का मतलब है कि संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है। पिछले दो हफ्तों में महाराष्ट्र में यह बढ़कर 1.08 हो चुकी है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर विशेषज्ञ कहने लगे है, अब तीसरी लहर आने से रोकना मुमकिन नहीं है। साथ ही वे दिलासा दे रहे हैं कि गंभीर खतरे जैसी कोई बात नहीं है। उनके मुताबिक, साप्ताहिक मामलों और आर-नॉट वैल्यू में उछाल संकेत देते हैं कि अगले महीने कोरोना का ग्राफ कैसा रहने वाला है। शेष@पेज 07

दो गज दूरी है जरूरी | जम्मू में ओमिक्रॉन के बाद तारबंदी

जम्मू में बुधवार को ओमिक्रॉन के तीन संक्रमित मिलने के बाद बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगाए गए तार।

शीर्ष पांच बीमारियों से मौतें...

बीमारी	मौतें	प्रतिशत
अस्कीमेक हार्ट डिजीज	1.52 करोड़	15.4 %
स्ट्रोक	10.92 करोड़	11.1 %
सीओपीडी	54.65 करोड़	5.5 %
कोविड 19	45.50 करोड़	4.6 %
रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन	41.50 करोड़	4.2 %

कम्यूनिटी ट्रांसमिशन शुरू

देश में शुरुआती ओमिक्रॉन केस विदेश से लौटे या उसके संपर्क में आने वाले शख्स तक सीमित थे। लेकिन अब बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले भी ओमिक्रॉन की चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली में 3 मामले ऐसे हैं, जिनमें मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इससे यह आशंका गहरा गई है कि ओमिक्रॉन का कम्यूनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। यह स्थानीय स्तर पर फैलने लगा है।

वैरिएंट ने रूप बदला तो चिंता की बात

नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने कहा, हम ओमिक्रॉन पर नजर बनाए हुए हैं। इसके स्वरूप में किसी भी तरह का बदलाव होता है तो चिंता की बात होगी।

एम्स निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा, ओमिक्रॉन की रोकथाम के सिर्फ दो तरीके हैं। पहला टीका और दूसरा कोविड नियमों का पालन।

महाराष्ट्र ओमिक्रॉन बढ़ा, तो राज्य में फिर बंद हो सकते हैं स्कूल

दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए किसी भी जमावड़े पर रोक लगा दी है। प्रशासन से रोजाना रिपोर्ट देने को कहा है।

पीएम मोदी आज करेंगे समीक्षा: ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ी चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बैठक करने वाले हैं। इसमें देश में कोरोना के हालात की समीक्षा के साथ ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

आंकड़ों से खुलासा | मौतों में कोरोना चौथे स्थान पर

ज्यादा डर कोरोना का, पर मौतें हार्ट डिजीज से

नई दिल्ली@पत्रिका. दुनियाभर में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर डर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कोरोना की अपेक्षा अन्य बीमारियों से मौतें ज्यादा हो रही हैं। दुनिया में शीर्ष 5 बीमारियों से होने वाली मौतों में कोरोना चौथे नंबर पर है। बीमारियों से मौतों की सबसे बड़ी वजह हार्ट और श्वसन संबंधी बीमारियां हैं। बचाव के कदमों से इन बीमारियों से मौतों की सख्या में 20 फीसदी तक कमी हो सकती है। दुनिया में 2020 में सबसे अधिक 16 फीसदी यानी 89 लाख मौतें हार्ट संबंधी बीमारियों से हुईं।

स्मोकिंग छोड़ने से 20% तक कम होंगी मौतें

पौष्टिक खानपान रखें। नियमित 45 मिनट पसीना आने तक व्यायाम करें। सिर्फ स्मोकिंग की लत छोड़ने से 10 फीसदी हार्ट संबंधी बीमारियों व 20 फीसदी श्वसन संबंधी बीमारियों से मौतें कम हो सकती हैं। कोविड संबंधी प्रोटोकाल का पालन जरूरी है।
– डॉ. एम, वली, कॉर्डियोलॉजिस्ट, नई दिल्ली

भोपाल में कोरोना पीड़ित मरीज की मौत

भोपाल. हमीदिया अस्पताल में मंगलवार रात कोरोना पीड़ित मरीज की मौत हो गई। वह होशंगाबाद जिले का रहने वाला था। एक सप्ताह से भर्ती था। डॉक्टरों के अनुसार, मरीज को लिवर, किडनी और डायबिटीज भी थी। इधर राजधानी में बुधवार को कोरोना के 11 नए मरीज सामने आए। यह लगातार दूसरा दिन है जब मरीजों की संख्या 10 से ज्यादा है। वहीं, राज्य में 19 संक्रमित मिले।

पतंग लूटने को दौड़ा बच्चा 25 फीट की ऊंचाई से गिरा, मौत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. पतंग लूटने के लिए दौड़ा 10 साल का बच्चा बुधवार को 25 फीट ऊंची छत से नीचे गिर गया। परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पिता दिनेश रंगीले ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने बेटे पुष्पेंद्र उर्फ प्रिंस के इलाज में देरी की। बाद में मौत पर होने पर बिल जमा कराने का दबाव बनाते हुए शव नहीं दिया। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने शव दिलाया। पुष्पेंद्र के माता-पिता बरखेड़ा पठानी में रहते हैं। दो दिन पहले बच्चा अपने ताऊजी के मकान में रहने गया था। पतंग लूटने के चक्कर में पुष्पेंद्र परिजनों को बिना बताए छत पर चला गया था।

बर्बरता ऐसी... पैरों में कीलें ठोंकी

बाड़मेर@पत्रिका. राजस्थान में आरटीआइ कार्यकर्ता अमर गोदारा (30) का अपहरण कर जान लेने की कोशिश का मामला सामने आया है। अमर के पांवों में पेचकस से वार किया गया। आरोपियों ने कीलें तक ठोंक दी। उसे घायल अवस्था में जोधपुर रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

एमपी-पीएससी: 24 अप्रेल को होगी प्रारंभिक परीक्षा

27% ओबीसी आरक्षण संग राज्य सेवा परीक्षा का ऐलान

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

इंदौर. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपी-पीएससी) ने बुधवार को राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा-2021 की अधिसूचना जारी कर दी। दोनों भर्ती परीक्षाओं के जरिए 300 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होंगी। प्रारंभिक परीक्षा 24 अप्रेल को होगी। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी होने तक पदों में इजाफा होने की उम्मीद है।

राज्य सेवा परीक्षा में 283 पद हैं। इनमें डिप्टी कलेक्टर के 27 व डीएसपी के 15 पद हैं। राज्य वन सेवा के जरिए सहायक वन संरक्षक के 8, वनक्षेत्रपाल के 40 और परियोजना क्षेत्रपाल के 15 पदों पर नियुक्ति की जानी है। राज्य सेवा व वन सेवा परीक्षा के आवेदन 10 जनवरी से 9 फरवरी भरे जाएंगे।

2019-20 के नहीं हो पाए परिणाम घोषित

पीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। मालूम हो कि ओबीसी आरक्षण 14% से 27% किए जाने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई है। इससे राज्य सेवा परीक्षा 2019 का मुख्य और राज्य सेवा परीक्षा 2020 का प्रारंभिक परीक्षा का नतीजा घोषित नहीं हुआ है।

निर्वाचन आयोग: सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए

पंचायत चुनाव होंगे, नतीजे तीनों चरणों के एक साथ ही

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे, लेकिन किसी भी सीट का परिणाम घोषित नहीं होगा। यह निर्णय उस स्थिति के मद्देनजर लिया है, जिसमें फिलहाल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सीटों पर चुनाव नहीं होने हैं। सभी सीटों पर परिणाम एक साथ घोषित किए जाएंगे।

प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान 6 जनवरी और दूसरे चरण के लिए 28 जनवरी को होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दूसरे चरण के मतदान के ठीक एक दिन पहले यानी 27 जनवरी को आएगा। क्योंकि ओबीसी सीटों के नामांकन और निर्वाचन प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रोक लगी हुई है, इसके चलते इन सीटों पर चुनाव-मतदान प्रक्रिया तीसरे चरण के साथ होना संभावित है।

सीलबंद किए जाएंगे सभी दस्तावेज

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा, शीर्ष कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव में सभी पदों के लिए मतगणना का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधी कार्यवाही स्थगित रहेगी। मतगणना से संबंधित सभी दस्तावेज अभ्यर्थियों और अभिकर्ताओं की मौजूदगी में सीलबंद कर किए जाएंगे।

कैग की रिपोर्ट: खाद्य सुरक्षा पर सरकार कठघरे में

सेहत से खिलवाड़, सरकार ने अदालत में नहीं की 'अपील'

पत्रिका एक्सक्लूसिव

नितिन त्रिपाठी
patrika.com

ग्वालियर. सेहत और जनजीवन से खिलवाड़ के मामलों में सरकार लापरवाह है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जितने केस आए, उनमें सरकार ने अपील करने की जहमत नहीं उठाई। ग्वालियर, मुरैना, सतना, भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, उज्जैन और खरगोन जिलों में से 5 जिलों में 217 गंभीर केस थे। इसके बावजूद अपील नहीं की। तीन जिलों ने जानकारी तक नहीं दी। ग्वालियर, मुरैना, भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, उज्जैन और खरगोन में ही इन वर्षों में लंबित अपील प्रकरणों में 416 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन को लेकर सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर तैयार 2021 की यह रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई है। लेखा परीक्षा के अनुसार, फरवरी 2020 तक ग्वालियर, मुरैना, सतना, भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, उज्जैन और खरगोन में 11851 लाइसेंस और 52266 रजिस्ट्रेशन की वैधता समाप्त हो गई थी। इसके बाद भी यह कारोबार करते रहे। खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई।

प्रकरण पेश करने में 35 महीने तक विलंब

ग्वालियर, मुरैना, भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, उज्जैन और खरगोन में 1800 मामलों में से 814 मामले अदालत में 35 माह तक की देरी से पेश किए गए। इनमें से 65 मामले एक साल से अधिक विलंब से पेश किए। इस देरी के लिए कलेक्टर की अनुमति जरूरी होती है, लेकिन इस अनुमति का प्रमाण लेखा परीक्षा को नहीं दिया गया।

अलग अधिकरण, न्यायालय स्थापित नहीं

सरकार की मंशा पर अपील प्रकरणों के आधार पर भी सवाल उठता है। 2011 से 13 के बीच उच्च न्यायालय में केवल 60 प्रकरणों में अपील की गई। यही नहीं 2014 से 19 के दौरान जिलावार अपील प्रकरणों का रिकॉर्ड तक है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा अपील प्रकरणों के लिए अलग से अधिकरण और न्यायालय की स्थापना तक नहीं की।

3169 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार

फूड पॉइजनिंग के 3169 मामले 2014 से पांच साल में सामने आए। ग्वालियर में 460, इंदौर में 1908, खरगोन में 108, उज्जैन में 574 और होशंगाबाद में 119 मामले थे।

इन खामियों का भी रिपोर्ट में जिक्र

- खाद्य विभाग में 771 पदों की आवश्यकता थी, सिर्फ 424 पद यानी 55% को स्वीकृत किया गया।
- फरवरी 20 की स्थिति में स्वीकृत पदों में सिर्फ 165 ही भरे थे, जबकि 259 पद (61 प्रतिशत) खाली पड़े थे।
- औद्योगिक इकाइयों और खाद्य कारोबारियों का सर्वे नहीं किया। इसलिए ये कानून के दायरे में नहीं आ सके।
- खाद्य लाइसेंस और पंजीयन का डेटा नहीं होने से इनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकी।
- इसके साथ ही मुखबिरों को इनाम देने के लिए निर्धारित कोष का गठन नहीं किया गया।

बजट के बड़े हिस्से का उपयोग तक नहीं

पांच साल में विभाग को 88 करोड़ से अधिक बजट मिला, लेकिन इसमें से महज 53 करोड़ 34 लाख ही खर्च किया गया। इसको माना गया कि खाद्य सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में नहीं है।

प्रदेश के इन्हीं 8 जिलों को ऑडिट के लिए इसलिए चुना

इंदौर, भोपाल, उज्जैन: खाद्य कारोबारियों की अधिकतम संख्या और दुग्ध उत्पादन के आधार पर

होशंगाबाद, सतना, खरगोन: धार्मिक महत्व के स्थलों पर खाद्य विक्रेताओं की संख्या के आधार पर

ग्वालियर और मुरैना: मीडिया रिपोर्ट में दुग्ध उत्पादों में मिलावट के अत्याधिक जोखिम के आधार पर

खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

(इन जिलों में संबंधित विभागों और न्यायालयीन प्रकरणों के दस्तावेज की जांच की गई)

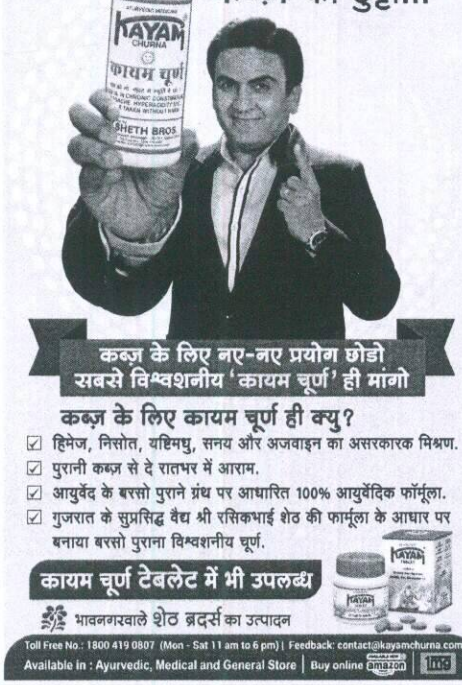

कायम चूर्ण करे, कब्ज़ की छुट्टी...

कब्ज़ के लिए नए-नए प्रयोग छोड़ो सबसे विश्वशनीय 'कायम चूर्ण' ही मांगो

कब्ज़ के लिए कायम चूर्ण ही क्यु?
- हिमेज, निसोत, यष्टिमधु, सनय और अजवाइन का असरकारक मिश्रण.
- पुरानी कब्ज़ से दे रातभर में आराम.
- आयुर्वेद के बरसो पुराने ग्रंथ पर आधारित 100% आयुर्वेदिक फॉर्मूला.
- गुजरात के सुप्रसिद्ध वैद्य श्री रसिकभाई शेठ की फार्मूला के आधार पर बनाया बरसो पुराना विश्वशनीय चूर्ण.

कायम चूर्ण टेबलेट में भी उपलब्ध

भावनगरवाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन

Toll Free No.: 1800 419 0807 (Mon - Sat 11 am to 6 pm) | Feedback: contact@kayamchurna.com
Available in : Ayurvedic, Medical and General Store | Buy online amazon | 1mg

फिर कैसे ओडीएफ फ्री | संसद में सरकार की दी जानकारी में खुलासा

2.86 लाख आंगनबाड़ी व 38 हजार स्कूलों में नहीं शौचालय

2.86 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी

गोविंद अग्निहोत्री
patrika.com

भोपाल. 'इज्जतघरों' के साथ देश खुले में शौच से मुक्त हो गया है। केंद्र सरकार ने अभी तक 711 जिलों और 6 लाख से ज्यादा गांवों को ओडीएफ फ्री घोषित किया है। हालांकि, सवाल उठ रहा है कि यह दावा सिर्फ कागजी तो नहीं? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देश के 38,408 सरकारी स्कूलों और 2.86 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में अब भी शौचालय चालू हालत में नहीं हैं। यह स्थिति तब है, जब महामारी फिर से सिर उठा रही है। शौचालयों की उक्त जानकारी हाल ही राज्य सभा में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने दी है।

आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय सुविधा का अभाव

राज्य	संख्या	राज्य	संख्या
महाराष्ट्र	53,496	कर्नाटक	13,518
ओडिशा	40,444	उत्तरप्रदेश	12,891
राजस्थान	29,098	झारखंड	12,883
असम	22,819	छत्तीसगढ़	4,151
प. बंगाल	20,884	मध्यप्रदेश	3,117
तेलंगाना	18,072	गुजरात	1,562
आंध्रप्रदेश	14,371		

राज्यसभा में दी गई जानकारी

स्कूलों की बात: राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार देश के 38,408 स्कूलों में शौचालय उपयोग लायक ही नहीं हैं। कोरोना संक्रमण के बीच चिंता का विषय है कि 2,85,103 स्कूलों में हाथ धोने तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 650,481 स्कूल पेयजल के लिए हैंडपंप पर निर्भर हैं।

बोतलबंद पानी के सहारे पर स्कूल

आंकड़ों से पता चलता है कि देश के 68,374 स्कूल पेयजल के लिए पैकेज्ड या बोतल के पानी पर निर्भर हैं। आंध्रप्रदेश में चितूर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे स्कूलों की संख्या 4190 है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। राजस्थान के डूंगरपुर ग्रामीण में 109 स्कूल, जयपुर ग्रामीण में 100 स्कूल ऐसे हैं। मध्यप्रदेश के गुना ग्रामीण में 129, छिंदवाड़ा में 51, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में 55 और महासमुंद ग्रामीण में ऐसे 20 स्कूल हैं।

5 साल में हर एक गांव में बनना था खेल मैदान, 14 साल में बने सिर्फ 253

कैग रिपोर्ट में खुलासा : करोड़ों फूंकने के बाद भी खेल विभाग की अधूरी रही योजनाएं

भोपाल निप्र

प्रतिभावान खिलाड़ियों की राज्य में कमी नहीं है। इन्हे तलाशने और तराशने की जरूरत है। इसी मंशा के चलते राज्य की शिवराज सरकार ने पांच साल की समय सीमा में प्रत्येक गांव में एक खेल मैदान विकसित करने की योजना बनाई थी। इसकी सफलता और असफलता का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2005 से 2019 के बीच 54 हजार गांवों में से सिर्फ 253 खेल मैदान ही विकसित हो पाए हैं। इसका खुलासा मप्र विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पटल पर रखी गई सीएजी रिपोर्ट में हुआ है।

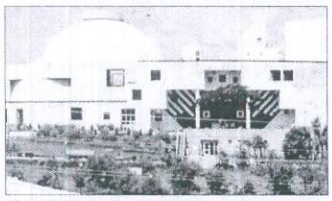

सफेद हाथी बना राज्य का खेल विभाग

खेल विभाग ने 2014 से 19 के बीच 15 आदिवासी बाहुल्य जिलों में एक भी खेल अकादमी स्थापित नहीं की, जबकि जनजातीय आबादी में छिपी प्रतिभाओं का पता लगाने के उपायों की बात कही गई और जनजाति उपयोजना के तहत 36.41 करोड़ रुपए खर्च भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक खेल विभाग की अधोसंरचना अनुपयोगी रही क्योंकि कार्य अधूरे रहे, खेल मैदान की स्थिति खराब रही, मिनी स्टेडियम का अधूरा रखरखाव होता रहा और आवश्यक उपकरणों की खरीदी नहीं होने, संधारण, कर्मचारियों को कार्य पर लगाए जाने में देरी के चलते विभाग अपने लक्ष्य से भटकता रहा। 18 खेल अकादमी में 65 प्रतिशत प्रशिक्षकों की कमी है।

पुलिस व्यवस्था

कैग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल किया है, उसने पाया कि 20.68 प्रतिशत रिक्त पदों के साथ गृह विभाग संघर्षरत रहा, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भर्ती के लिए मांग प्रेषित करने में विलंब किया, कुछ स्थानों को छोड़कर ज्यादातर थानों में मानव शक्ति की कमी देखी गई, पुलिस लाइन में स्वीकृत मानव शक्ति से 37.67 प्रतिशत अधिक कर्मचारी थे, विभाग अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षा गार्डों के प्रावधान को विनियमित करने और गैर आवश्यक सुरक्षा बंद करने में भी विफल रहा, जिससे पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबी पुलिस और दबती गई।

मुफ्त अनाज योजना में गड़बड़ी

सरकार की मुफ्त अनाज योजना में भी कैग को ढेरों अनियमितताएं मिली हैं और कैग ने सुझाव भी दिया है, कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा ढांचे में कमी के कारण मध्यप्रदेश शासन ने फरवरी 2020 तक अपीलीय और गंभीर प्रकरणों, जिसमें जिला और सत्र न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित रहने में वृद्धि के बावजूद अलग से खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण और अपराधों की सुनवाई के लिए अलग से विशेष, साधारण न्यायालय की स्थापना नहीं की। जोकि नियमों के तहत आवश्यक था।

3.64 करोड़ जुर्माना नहीं वसूल पाया

विभाग के प्रशासकीय तंत्र में भी कमी थी क्योंकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अधिकारियों सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर अतिरिक्त प्रभारी के रूप में लोगों को बैठाया गया, विभाग में 61 प्रतिशत मानव शक्ति की कमी रही, विभाग अर्थदंड की राशि 3.64 करोड़ भी नहीं वसूल सका और दोषियों के विरुद्ध राजस्व वसूली प्रमाण पत्र की कार्रवाई भी शुरू नहीं कर सका।

कैग ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य के लिए एक मजबूत परीक्षण आधारित संरचना का होना स्वभाविक है, इंदौर-उज्जैन की खाद्य प्रयोगशालाओं को अपग्रेड भी नहीं किया गया, जिसने खाद्य विश्लेषकों के कार्य को प्रभावित किया।

विज्ञान यात्रा से स्थानीय प्रतिभाओं को पहचानने में मिलेगी मदद

भारत में प्रकृति के शोषण नहीं, दोहन का दर्शन : शिवराज सिंह

भोपाल निप्र

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हमें वैज्ञानिक विकास से उत्पन्न परिस्थितियों को भी समझना होगा। कोरोना पर स्थिति हमारे सामने हैं, इसके साथ कैंसर एक्सप्रेस की बातें भी सुनाई दे रही हैं। भारत में प्रकृति के शोषण के स्थान पर प्रकृति के दोहन का दर्शन था। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों में काम कर रही महिलाओं को यदि थोड़ा विज्ञान और तकनीक का सहयोग मिल जाए, तो उनके उत्पाद बेहतर हो सकते हैं। उत्पादों की उपयोगिता और गुणवत्ता में सुधार आ सकता है।

यह बात शिवराज ने बुधवार को मध्यप्रदेश विज्ञान सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का मंत्रालय से वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करते हुए कही। यहां शिवराज ने कहा कि यह सम्मेलन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मेप बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। धर्म और विज्ञान एक दूसरे का समर्थन करते हैं। मंत्र भी एक विज्ञान है, ध्वनि ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। मंत्रों के चमत्कार विज्ञान ने सिद्ध किए हैं। भारत ने खगोल विज्ञान, गणित आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, भास्कराचार्य जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ हमारे यहाँ हुए हैं। शून्य का आविष्कार भी भारत में हुआ। गणित और विज्ञान में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत खगोल विज्ञान, गणित और आध्यात्म के क्षेत्र में लगातार आगे रहा है। विज्ञान के सहयोग से प्रदेश में अपार संपदा का उपयोग कर हम रोजगार के अवसर सृजित कर सकते हैं। सीएम राइज स्कूल में सभी विषयों के साथ विज्ञान के अध्ययन के लिए भी समुचित व्यवस्था रहेगी।

शिवराज ने कहा कि कृषि के मामले में हमें परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है। रासायनिक खाद ने हमारे अन्न और सब्जियों को विषाक्त कर दिया है। परिणामस्वरूप ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे समुद्र का जल-स्तर तो बढ़ेगा ही साथ ही नदियाँ भी प्रभावित होंगी। केवल तकनीक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। भारत में प्रकृति पूजा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम थी।

मुख्यमंत्री चौहान ने विज्ञान भारती मालवा टीम को बधाई देते हुए कहा कि इस आयोजन से जो निष्कर्ष निकलेंगे उनके क्रियान्वयन के लिए वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेट्स और अधिकारियों की एक टीम बनाई जाएगी।

पुलिस को दस हजार में पड़ी युवक के साथ मारपीट

भोपाल निप्र

एक युवक के साथ गाली-गलौच, मारपीट व झूठे केस में फंसाने की धमकी देना महंगा पड़ गया है। क्योंकि मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में फरियादी को दस हजार रुपए बतौर जुर्माना देने के निर्देश पुलिस विभाग को दिया है। साथ ही सहूलियत भी दी है कि चाहे तो यह राशि दोषियों से वसूलकर पीड़ित के खाते में जमा कराई जा सकती है।

मानवाधिकार आयोग ने फरियादी को दस हजार रुपए देने का निर्देश पुलिस विभाग को दिया

मामला भिंड जिले का है। जहां थाना एंडोरी में पदस्थ कार्यवाहक उप निरीक्षक रमेश चन्द्र माहौर एवं कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक गजेन्द्र सिंह चौहान ने संतोष सिंह तोमर के साथ अभद्रता की थी। साथ हुई घटना में मारपीट की रिपोर्ट करने के बाद, थानास्तर पर विधिसम्मत कार्यवाही नहीं करने तथा आवेदक के मानव अधिकारों के हनन के लिये आयोग का दरवाजा खटखटाया था।

वहीं ग्वालियर जिले से जुड़े एक अन्य मामले में आयोग ने विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुरूपयोग करने के लिये उप निरीक्षक जेएस मुजोरिया एवं सहायक उप निरीक्षक आरपी गुनकर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये कहा है।

वर्चुअली शामिल हुए मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। मंत्रालय कक्ष में वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन का श्रवण किया। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, प्रमुख सचिव जनसंपर्क शिव शेखर शुक्ला और आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े उपस्थित थे।

पंचायत चुनावः आयोग ने किया मेडिकल बोर्ड का गठन, जारी किए कई दिशा निर्देश

भोपाल निप्र

प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए अब तक 2 लाख 15 हजार 35 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। 23 दिसंबर तक उम्मीदवारी से नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने निविदा, स्वीकृति एवं क्रय की अनुमति के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि जिला अधिकारी निविदा स्वीकृति या क्रय के प्रस्ताव सीधे न भेजें। पंचायत अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका पुस्तिका सभी जिला कलेक्टरों को उपलब्ध करवा दी गई है। इधर, बालाघाट में सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है।

अब सीधे प्रस्ताव नहीं भेज पाएंगे अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग सचिव बीएस जामोद ने जानकारी दी है कि पंचायत चुनाव में प्रथम और द्वितीय चरण के लिए 23 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थिता से नाम वापस लिए जा सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के तत्काल बाद से 23 दिसंबर को अपरान्ह 3 बजे तक कार्यालयीन समय में कभी भी अभ्यर्थिता से नाम वापस ले सकता है। पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के लिये ऑनलाइन नाम-निर्देशन नामक अभ्यर्थी के लिये मार्गदर्शिका पुस्तिका का शासकीय केन्द्रीय मुद्रा भोपाल के माध्यम से जिले के समस्त कलेक्टरों को उपलब्ध कराई गई है। पुस्तिका का मूल्य 10 रूपये निर्धारित किया गया है। पुस्तिका जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य को ही विक्रय की जाना है। आवश्यकतानुसार ऑनलाइन नाम-निर्देशन पुस्तिका संबंधित रिटर्निंग ऑफीसरों से खरीदी जा सकती है।

रानी कमलापति की तर्ज पर बनेगा इंदौर का रेलवे स्टेशन

इंदौर स्व.स.से.

इंदौर से भाजपा सांसद शंकर लालवानी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रानी कमलापति के बाद अब इंदौर रेलवे स्टेशन का भी आधुनिकीकरण होगा। इंदौर रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप होगा। स्टेशन पर हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट जैसी सारी सुविधाएं मिलेंगी।

दरअसल, इंदौर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए सांसद शंकर लालवानी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। बैठक में इंदौर रेलवे स्टेशन के री डेवलपमेंट को लेकर और बस एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करने की चर्चा हुई। रेलवे स्टेशन का री डेवलपमेंट आने वाले 50 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर होगा।

वन मंत्री विजय शाह ने विधानसभा में दी जानकारी

प्रदेश में दो साल में 71 बाघों की मौत, इनमें से 20 का शिकार

भोपाल निप्र

मध्य प्रदेश में बीते दो साल में 71 बाघों की मौत हुई है। इसमें से 20 बाघों का शिकार हुआ है। यह जानकारी बुधवार को वनमंत्री विजय शाह ने विधायक नारायण सिंह पट्टा के सवाल के जवाब में विधानसभा में दी।

वनमंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि पिछले वर्ष एक जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश में 30 बाघों की मौत हुई है। इनमें से नौ मामले शिकार के हैं। टाइगर रिजर्व में 19 बाघों की स्वाभाविक मौत हुई है और दो बाघों का शिकार हुआ है, जबकि संरक्षित क्षेत्र में दो बाघों की स्वाभाविक मौत दर्ज की गई है और सात बाघों का शिकार हुआ है।

वन मंत्री ने इस वर्ष के आंकड़े पेश करते हुए बताया कि एक जनवरी से सात दिसंबर 2021 के बीच 41 बाघों की मौत की पुष्टि की है। इनमें से 11 बाघों का शिकार हुआ है। टाइगर रिजर्व में 20 बाघों की स्वाभाविक मौत हुई है और पांच बाघों का शिकार हुआ है, जबकि संरक्षित क्षेत्रों में छह बाघों का शिकार और 10 की स्वाभाविक मौत दर्ज की गई है।

23 महीने में रातापानी में दो और सिंघौरी में एक बाघ की मौत

विधायक डा. सतीश सिकरवार के सवाल के जवाब में वनमंत्री विजय शाह ने जानकारी दी कि जनवरी 2020 से नवंबर 2021 के बीच रातापानी अभयारण्य में दो और सिंघौरी अभयारण्य में एक बाघ की मौत हुई है। विधायक ने प्रदेश के विभिन्न अभयारण्यों में जनवरी 2020 से नवंबर 2021 तक बाघ-बाघिन की मौत की जानकारी मांगी थी। विधायक के एक अन्य सवाल के जवाब में वन मंत्री ने बताया कि वर्तमान वर्ष में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के बरौली घाट से घड़ियाल के दो सौ अंडे इकट्ठा किए गए हैं।

सुडोकु-1564

सरल

3				8				9
		8	6		9	5		
6	5			4			7	1
	4						2	
1	2			6			9	8
		6	4		5	8		
9				1				7

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भर जाने आवश्यक है.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में तथा 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सुडोकु-1563

8	2	4	3	9	7	5	1	6
3	5	6	1	4	2	7	8	9
1	9	7	6	5	8	2	3	4
9	6	2	5	8	3	1	4	7
5	3	1	4	7	9	8	6	2
4	7	8	2	1	6	9	5	3
2	8	3	9	6	1	4	7	5
6	1	5	7	2	4	3	9	8
7	4	9	8	3	5	6	2	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

अंतिम दिन 'वारतां विक्रमाजीत दी' की हुई प्रस्तुति

भोपाल निप्र

'वारतां विक्रमाजीत दी' की प्रस्तुति के साथ महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ का प्रतिष्ठा आयोजन तीन दिवसीय विक्रमोत्सव-2021 का आज औपचारिक समापन हो गया। एक लम्बी खामोशी के बाद भोपाल में रंग गतिविधियों का आरंभ विक्रमोत्सव-2021 से हुआ। भारी ठंड के बीच भी कलारसिकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। तीनों दिन नाट्य प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में कलारसिकों की भागीदारी दिखी।

विक्रमोत्सव-2021 का हुआ समापन

विक्रमोत्सव 2021 के प्रथम दिन महानाट्य 'सम्राट विक्रमादित्य' की प्रस्तुति रंग निर्देशक संजीव मालवीय के निर्देशन में हुई। यह महानाट्य कभी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हुआ था जिसे कोविड के बाद उपजी स्थितियों के उपरांत निर्देशक संजीव मालवीय ने पारम्परिक और थ्रीडी सिस्टम में समेट कर तीन घंटे के नाटक को करीब दो घंटे की अवधि में प्रस्तुत कर अपनी निर्देशकीय कौशल का परिचय दिया। कोविड के बाद सुस्त पड़ी रंग गतिविधियों की विक्रमोत्सव 21 के माध्यम से शुरूआत हुई तो कला रसिकों का प्रतिसाद भी मिला। कड़ाके की ठंड के बावजूद दर्शकों से हॉल भरा रहा।

इसी कड़ी में दूसरी प्रस्तुति मालवा की माच शैली में खेल माच का 'राजा विक्रम' की प्रस्तुति पंडित ओमप्रकाश शर्मा के निर्देशन में हुई। विक्रमोत्सव 2021 की तीसरी और अंतिम प्रस्तुति 'वारतां विक्रमाजीत दी' की थी। वरिष्ठ नाट्य निर्देशक राजीव सिंह की यह प्रस्तुति पंजाबी लोकगीतों में विक्रमादित्य को खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के माध्यम से यह बात भी स्थापित हो जाती है कि विक्रमादित्य की कीर्ति केवल मालवाचंल ही नहीं, बल्कि देश के हर राज्य में है।

विक्रमोत्सव-2021 समापन के बाद चर्चा करते हुए महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने बताया कि विक्रमोत्सव अब देश के प्रमुख शहरों अयोध्या, पटना, बनारस, आगरा, मथुरा, चंडीगढ़, पुणे, जयपुर, दिल्ली एवं बैंगलरु में आयोजित किया जाएगा। साथ ही 'भारत विक्रम' शीर्षक से ।। भारत उत्कर्ष एवं नव-जागरण पर केन्द्रित यह व्याख्यान माला देश के प्रमुख शहरों में भी आयोजित किये जाने की योजना है। यह बात महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने पत्रकारों से कही। श्री तिवारी ने कहा कि विक्रमोत्सव देश के अन्य शहरों में किये जाने का उद्देश्य विक्रम कीर्ति से समाज का परिचय कराना है। विक्रम कीर्ति सार्वभौमिक रही है और यही बात समाज तक पहुंचाना है।

टीकाकरण महाअभियान में आज फिर मिली बड़ी सफलता

भोपाल निप्र

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश की जागरूक जनता को धन्यवाद दिया है, जिनके सहयोग से आज टीकाकरण महाअभियान-11 में 11 लाख 44 हजार से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई गई। वैक्सीनेशन में मध्यप्रदेश लगातार रिकार्ड कायम कर रहा है। आज प्रदेश में 10 करोड़ वैक्सीन डोज लगने का रिकार्ड भी बना है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने में भी मध्यप्रदेश देश में अग्रणीय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों की जागरूकता और सक्रियता से वैक्सीनेशन कार्य में मिली इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

प्रदेश ने बनाया 10 करोड़ टीका लगाने का रिकार्ड

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शत-प्रतिशत टीकाकरण के लिये निरंतर चलाये जा रहे महाअभियानों से हम शीघ्र ही शत-प्रतिशत पात्र लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाना सुनिश्चित कर लेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्य में जनता का सहयोग भी जरूरी है। टीकाकरण महाअभियान-11 में रात्रि 9 बजे तक 11 लाख 44 हजार 361 नागरिकों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जल्द से जल्द प्रदेश के सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान की शृंखला चलाई जा रही है।

शब्द पहेली - 1564

आ	क	मु	ग	ल	ए	अ	ला	तु	र	द
द	ह	ल	प्र	व	बु	स	द	ह	को	इ
र	स	म	म	दी	छ	ल	आ	मं	ख	क
इ	स	ल	द	दि	वा	स	ख	ल	श	क
हि	आ	दा	ग	न	ज	मा	प	णा	झ	ड़
व	ला	द	र	दि	ग	उ	र	ण	दे	क
ती	व	ग	मी	या	प	र	भ	नां	व	को
सां	ए	ऊ	पु	द	व	क	णी	ए	श	ल्हा
क	ग	ल	प	ह	गौ	स	री	आ	प	पु
क	ग	ली	प	लि	जौ	त	ए	आ	प	र
प	अ	म	रा	व	ती	स	व	र्धा	प	भ

शब्द जाल में महाराष्ट्र के 10 जिलों के नाम ढूंढिए, नाम उपर से नीचे एवं तिरछे भी हैं.

अहमदनगर, अमरावती, नागपुर, वर्धा, बुलढाणा, लातुर, नांदेड़, कोल्हापुर, सांगली, परभणी

शब्द पहेली - 1563

Jagrutidaur.com, Bangalore

एनसीआरबी की रिपोर्ट : उत्तर प्रदेश-छत्तीसगढ़ की तुलना में प्रदेश में पुलिसकर्मी कम

भोपाल निप्र

उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान की तुलना में मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मी कम हैं और अपराध ज्यादा हैं। मध्य प्रदेश में एक लाख की आबादी पर 126 पुलिसकर्मी हैं, तो प्रति लाख 298 अपराध घटित हो रहे हैं। यह आंकड़े वर्ष 2019 के हैं, जो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट में सामने आए हैं। प्रदेश में पुलिस की इस स्थिति पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने भी टिप्पणी की है।

उनकी रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि पुलिस विभाग को वर्ष 2018 और 2019 में पांच हजार 750 सूबेदार, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक की भर्ती करना थी, जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की आड़ लेकर नहीं की गई। कैग ने इसके लिए सीधेतौर पर पुलिस मुख्यालय की कार्मिक शाखा को जिम्मेदार ठहराया है।

पांचों राज्यों में अपराध की स्थिति और प्रति लाख पुलिसकर्मी की उपलब्धता

राज्य	अपराध प्रति लाख	पुलिसकर्मी प्रति लाख
मध्य प्रदेश	298.3	126.12
उत्तर प्रदेश	156.3	129.84
महाराष्ट्र	278.4	172.42
राजस्थान	290.3	128.23
छत्तीसगढ़	212.3	234.92
भारत में	241.2	158.22

मध्य प्रदेश में अपराध दर पड़ोसी राज्यों की तुलना में तो अधिक है ही, राष्ट्रीय औसत 241.2 से भी अधिक है। जबकि पड़ोसी राज्यों की तुलना में प्रदेश में प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की उपलब्धता भी संतोषजनक नहीं है। यह भी राष्ट्रीय औसत 158.22 से कम है। जनवरी 2019 में एक लाख 28 हजार 287 पद स्वीकृत थे। इनके विरुद्ध एक लाख एक हजार 751 कर्मचारी कार्यरत थे। यानी विभाग में 20.68 प्रतिशत पद रिक्त थे।

भर्ती नियम बनाने में हुई देरी

समय से पुलिसकर्मियों की भर्ती नहीं होने के लिए पुलिस मुख्यालय भी बराबर का जिम्मेदार है। मुख्यालय ने भर्ती नियम बनाने में दो साल से ज्यादा समय लगा दिया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य शासन ने मुख्यालय के प्रस्ताव को अक्टूबर 2020 में मंजूर नहीं किया था, तो रिक्त पद भरने के लिए मौजूदा भर्ती नियमों को जारी रखना था।

नईदुनिया 9
ग्वालियर, गुरुवार 23 दिसंबर, 2021

उप्र-छत्तीसगढ़ की तुलना में मध्य प्रदेश के पास

पुलिस बल कम, अपराध ज्यादा

एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चली पुलिस बल व अपराध दर की स्थिति

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। प्रदेश के दो बड़े शहरों भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने वाली राज्य सरकार को प्रदेश में पुलिस बल की कमी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान की तुलना में मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मी कम हैं और अपराध ज्यादा हैं। प्रदेश में एक लाख आबादी पर 126 पुलिसकर्मी हैं, तो प्रति लाख आबादी पर 298 अपराध घटित हो रहे हैं। ये आंकड़े वर्ष 2019 के हैं, जो राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट में सामने आए हैं। प्रदेश में पुलिस की इस स्थिति पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने भी टिप्पणी की है। उनकी रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि पुलिस विभाग को वर्ष 2018 और 2019 में 5,750 सूबेदार, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक की भर्ती करनी थी, जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की आड़ लेकर नहीं की गई।

5,750
सूबेदार, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक की भर्ती नहीं प्रदेश में

पांचों राज्यों में अपराध की स्थिति और प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मी की उपलब्धता

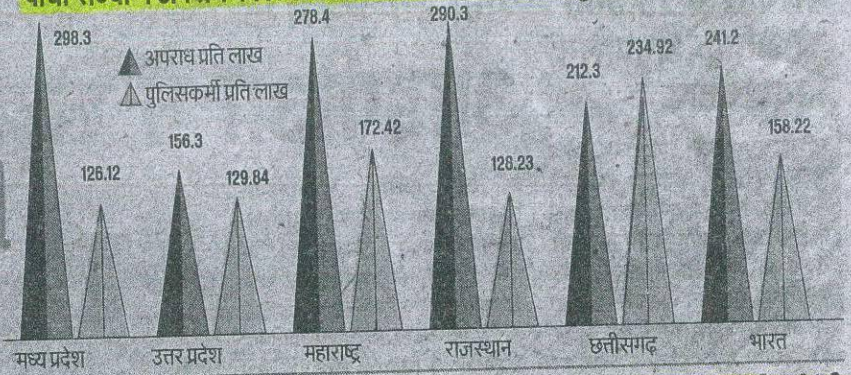

(स्रोत: एनसीआरबी)

5,750 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव ही नहीं भेजा

सितंबर, 2018 में मुख्यमंत्री ने थानों और पुलिस लाइन में बल बढ़ाने के लिए सूबेदार, उपनिरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक के 5,750 पद स्वीकृत किए थे। नए थानों-चौकियों की स्थापना के लिए भी बल की जरूरत थी। इन पदों पर दो चरणों में (3500 और 2250) भर्ती करनी थी। जांच से पता चला कि दिसंबर, 2019 तक विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। वहीं यह भी कहा गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण को लेकर स्थिति साफ नहीं थी।

भर्ती नियम बनाने में भी हुई देरी

कैग ने रिपोर्ट में कहा है कि समय से भर्ती नहीं होने के लिए पुलिस मुख्यालय भी बराबर का जिम्मेदार है। उसने नियम बनाने में दो साल से ज्यादा समय लगा दिया। राज्य शासन ने मुख्यालय के प्रस्ताव को अक्टूबर, 2020 में मंजूर नहीं किया था, तो रिक्त पद भरने के लिए मौजूदा भर्ती नियमों को जारी रखना था।

प्रदेश में अपराध राष्ट्रीय औसत से भी अधिक

मप्र में अपराध दर पड़ोसी राज्यों की तुलना में तो अधिक है ही, राष्ट्रीय औसत 241.2 से भी अधिक है, जबकि पड़ोसी राज्यों की तुलना में प्रदेश में प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की उपलब्धता भी संतोषजनक नहीं है। यह भी राष्ट्रीय औसत 158.22 से कम है। जनवरी, 2019 में 1 लाख 28 हजार 287 पद स्वीकृत थे। इनके विरुद्ध 1 लाख 1 हजार 751 कर्मचारी कार्यरत थे। यानी विभाग में 20.68 प्रतिशत पद रिक्त थे।

Name of Newspaper → दैनिक भास्कर

Date → 23/12/21

Page No → 02

इधर ग्वालियर में खाद्य विभाग की लापरवाही पर उठाए सवाल

ग्वालियर सहित कई जिलों में खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने, जुर्माना वसूलने में बरती लापरवाही

अभिषेक शर्मा | ग्वालियर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने बुधवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट में ग्वालियर, मुरैना सहित प्रदेश के कई ज़िलों में खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों से लेकर दूध तक के सैंपल लेने, उसकी रिपोर्ट देने से लेकर कारोबारियों पर जुर्माना करने और उसे वसूलने तक में लापरवाही बरते का ज़िक्र किया गया है। रिपोर्ट में बताया है कि वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 तक दोषी खाद्य कारोबारियों पर 5 करोड़ 53 लाख रुपए का जुर्माना लगा था, लेकिन विभागीय अधिकारी इनमें से 3.64 करोड़ रु. की वसूली तक नहीं कर पाए।

रिपोर्ट में भोपाल, खरगौन, उज्जैन, होशंगाबाद, इंदौर, सतना जिले भी शामिल हैं। कैग का मानना है कि मप्र शासन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन को लेकर ग्राउंड पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की। जिसके कारण इस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने वाले खाद्य कारोबारियों पर केस दर्ज करने और उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करने और उसे वसूल करने तक में लगातार देरी हुई है। रिपोर्ट में बताया है कि सैंपल लेने के बाद फूड लैब से उसकी जांच होने और उसकी रिपोर्ट से संबंधित खाद्य कारोबारियों को अवगत कराने में 2 दिन से लेकर 286 दिनों तक की देरी हुई। दोषी खाद्य कारोबारियों पर अभियोजन की कार्रवाई शुरू करने में 4 से 35 महीने की देरी हुई। शेष पेज 3 पर

ग्वालियर सहित...

ग्वालियर सहित इन सभी जिलों में 11 हजार 851 के लाइसेंस समाप्त हो गए और 52 हजार 266 कारोबारियों का पंजीयन की वैधता समाप्त हो गई। इसके बाद भी ये लोग कारोबार कर रहे थे या नहीं, इसकी जांच नहीं की गई।

Name of News paper - दैनिक भास्कर
Date → 23/12/21
Page No → 03

पुलिस थानों, चौकियों पर अमले की पोस्टिंग में अनियमितता, भर्ती में भी देरी: सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पुलिस विभाग 26 हजार 536 रिक्त पदों को भर्ती करने के लिए संघर्षरत रहा। लेकिन मप्र व्यापम को विभिन्न पदों की भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजने में ही 6 से 11 महीने लगा दिए। सितंबर 2018 में सृजित किए गए विभिन्न 5750 पदों को भी नहीं भर सका। वहीं ग्वालियर, बालाघाटा, भिंड, इंदौर, शिवपुरी जैसे जिलों में 158 पुलिस थानों, 69 चौकियों में 9 हजार 642 स्वीकृत अमले के विरूद्ध 2 हजार 648 कर्मचारी कम तैनात पाए गए। जबकि विडंबना यह रही कि इन जिलों की पुलिस लाइन में ही स्वीकृत 2 हजार 174 कर्मचारियों की तुलना में 819 कर्मचारी अधिक तैनात पाए गए।

सीएजी ने विशेष तौर पर उल्लेख किया है कि प्रदेश के 12 पुलिस थाने ऐसे पाए गए जहां पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं में सबसे अधिक केस दर्ज होना पाए गए, लेकिन उसकी तुलना में कर्मचारी स्वीकृत अमले के विरुद्ध 55 से 74 प्रतिशत कम संख्या में तैनात किए गए। जबकि यहां पर अधिक संख्या में पुलिसकर्मी तैनात होने चाहिए थे।

मौसम का मिजाज ग्वालियर

26.0°C अधिकतम | 6.0°C न्यूनतम

सूर्यास्त: आज शाम 17:31 बजे
सूर्योदय: कल सुबह 07:01 बजे
चन्द्रोदय: आज रात 22:06 बजे
चन्द्रास्त: कल सुबह 11:24 बजे

घनघोर जाड़ा फिर लौटेगा: ग्वालियर में न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज, तब भी सामान्य से एक डिग्री नीचे, प्रदेश के सबसे सर्द शहरों में आठवें स्थान पर

शीतलहर का असर कम होते ही दो दिन में रात का पारा 3.8 डिग्री बढ़ा

शीतलहर का असर कम होते ही अब रात का पारा तेजी से बढ़ने लगा है। इसके चलते तीन दिनों में ही पारा 3.8 डिग्री तक बढ़ने के बाद अब राहत मिलने लगी है।

आज पहुंच सकता है 10 डिग्री के करीब

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

ग्वालियर. बुधवार- गुरुवार की रात में तापमान 6 डिग्री तक पहुंचने से हल्की सी सर्दी कम रही। इसका असर गुरुवार को दिन में भी देखने को मिला। इसके साथ ही दिन में बादल छाए रहे। मौसम वैज्ञानिक एके शुक्ला शुक्रवार को रात का तापमान तेजी से बढ़ेगा। इसके चलते रात का तापमान 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं बादल छा सकते हैं। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा। गुरुवार को अधिकतम तापमान 26.0 और न्यूनतम 6.0 डिग्री दर्ज किया गया।

धूप से राहत

मौसम में आ रहे बदलाव के चलते गुरुवार को दिन में अच्छी धूप से लोगों को काफी राहत मिली है। इसके चलते लोगों ने घरों के बाहर निकलकर धूप का फायदा लिया। वहीं हवाएं भी नहीं चलने से लोगों को काफी सुकून मिला।

बारह घंटे का तापमान

सुबह 5.30	सुबह 8.30	सुबह 11.30	दोपहर 2.30	शाम 5.30
8.0°	8.6°	22.6°	25.2°	20.2°

ओस की बूंदों से बना बर्फ का जाल

शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक खेत में स्थित मकड़ी के जाल के ऊपर ओस की बूंदें जम गई.
फोटो: शशिभूषण पांडेय

न्यूज 2 मिनट में

आज इन क्षेत्रों में तीन घंटे गुल रहेगी बिजली

11 केवी सेवा नगर फीडर पर मेंटेनेंस कार्य होने के कारण शुक्रवार को तीन घंटे के लिए बिजली गुल रहेगी। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक फूलबाग चौराहा, खेड़ापति रोड, रवि नगर, खेड़ापति कॉलोनी, प्रेम नगर, द्वारिकापुरी, तुलसी विहार कॉलोनी, मरीमाता, ख्वाजा खानून आदि क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

विदेश से आए 16 लोगों के सैंपल लिए गए। विदेश से इन दिनों लगातार लोग आ रहे हैं। इसी के तहत 21 दिसंबर को ग्वालियर में आने वाले लोगों के घर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। जिसमें शहर के कई क्षेत्रों में जाकर 16 लोगों के सैंपल लिए गए।

चिकनगुनिया के दो और डेंगू का एक मरीज मिला

सर्दी के बढ़ते ही अब डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या कम हो गई है। गुरुवार को चिकनगुनिया के दो मरीज जीआरएमसी और मुरार जिला अस्पताल में आए हैं, इसमें एक युवक और दूसरा बच्चा है। वहीं मेडिकल कॉलेज में एक बच्चा डेंगू का आया है। इस तरह डेंगू के मरीजों की संख्या जिले में 2749 हो गई है।

13276 लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन

कोरोना के बचाव को लेकर लगाई जा रही वैक्सीनेशन में गुरुवार को 13276 लोगों को टीके लगाए गए। इसमें पहला डोज 939 और दूसरा डोज 12337 को लगाया गया। वहीं शुक्रवार को तीन सौ सेंटरों पर वैक्सीनेशन होगा।

तिघरा व मोतीझील प्लांट से आज जल प्रदाय रहेगा प्रभावित

ग्वालियर @ पत्रिका. तिघरा इनलेट चैंबर एवं कैनाल के बीच लाइनर गुरुवार को लगाया जाएगा। जिससे तिघरा डैम का गेट बंद रहेगा और तिघरा प्लांट से जल प्रदाय नहीं हो पाएगा। मोतीझील के दोनों प्लांट से भी आंशिक रूप से जल प्रदाय हो सकेगा। सहायक यंत्री जल प्रदाय सतीश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 160 एमएलडी से जल प्रदाय सुबह तक मोतीझील स्थित बैलेंसिंग टैंक में रॉ वॉटर के जल स्तर बढ़ने पर किया जा सकेगा। अभी बैलेंसिंग टैंक में जल स्तर 5 फीट है एवं 160 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बीते रोज 22 दिसंबर से चल रहा है।

नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया... लेकिन डबरा में तो प्लांट का काम ही नहीं हुआ

तीन ऑक्सीजन प्लांट में से एक शुरू नहीं, दो चलने के बाद बंद

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का डर बना हुआ है। इससे बचने के लिए पिछले काफी समय से तैयारी चल रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में लोगों को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। इसकी कमी के चलते कई मौत भी ऑक्सीजन न मिलने से हुईं।

जेएएच में चार महीने से बंद है एक प्लांट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

ग्वालियर. उसको देखते हुए जिलेभर में आठ महीने पहले ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहां अभी तक ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। अगर इस समय मरीजों की संख्या बढ़ जाए तो कई जगह ऑक्सीजन की काफी समस्या सामने आ जाएगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज की गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। इसके कभी भी गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।

जेएएच में चार में से दो ऑक्सीजन प्लांट शुरू।	एक हजार बिस्तर के अस्पताल में ट्रायल के बाद मरीज न आने से प्लांट किया बंद	सनफॉर्मा का ऑक्सीजन प्लांट अब बदला जाएगा	जिला अस्पताल में दो सौ प्रति मिनट ऑक्सीजन बनाता है

मंत्री, कलेक्टर की फटकार का नहीं असर

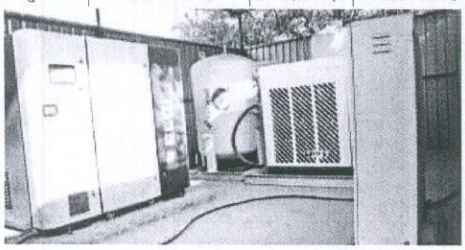

पिछले दो तीन महीने से प्रभारी मंत्री, केन्द्रीय मंत्री और कलेक्टर तक ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने के लिए अधिकारियों से कह चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कुछ प्लांट शुरू नहीं हो पाए हैं।

जेएएच के दो प्लांट बंद

जेएएच में कार्डियोलॉजी के सामने समफॉर्मा कंपनी का सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था। कुछ दिन लगने के बाद से ही यह प्लांट खराबी के चलते बंद पड़ा है। इसके साथ ही ट्रॉमा सेंटर के बाहर लगा प्लांट भी कई दिनों से बंद चल रहा है।

डबरा में काम ही शुरू नहीं हो सका

डबरा जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का काम अभी तक शुरू ही नहीं हो सका है। इसका कारण यह है कि यह प्लांट 45 लाख में लगना है, लेकिन इसके लिए 25 लाख का बजट आया है। ऐसे में यह अभी तक शुरू ही नहीं हो पाया है।

बजट कम होने से रुका काम

डबरा में ऑक्सीजन प्लांट के लिए बजट कम होने से काम रुका है। लेकिन इसके चलते वहां पर स्टोर टैंक में ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दी है।

डॉ. मनीष शर्मा, सीएमएचओ

जूडा की हड़ताल के पांच दिन... लगातार बिगड़ रहे हालात

हर दिन बीस से ज्यादा ऑपरेशन टल रहे, डॉक्टरों की छुट्टी रद्द

कई डॉक्टर नए साल में घूमने का कर रहे प्लान

मरीजों को लौटना पड़ रहा बिना इलाज के

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

ग्वालियर. जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के चलते अब जेएएच की व्यवस्था पर असर पड़ने लगा है। हड़ताल के चलते जहां मरीजों की जांचें तक अटक गई हैं। वहीं एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड के लिए भी मरीजों से मना किया जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा रुटीन के ऑपरेशन वाले मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। अब हालात यह हो गए हैं कि लगभग हर दिन 20 से ज्यादा ऑपरेशनों को टाला जा रहा है। जूडा की हड़ताल को देखते हुए तीन दिन पहले ही डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। ओपीडी और अन्य वार्डों में सीनियर डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर न होने से मरीजों की देखरेख सही से नहीं हो पा रही है।

खबर को विस्तार से पढ़ें patrika.com

ईयर एंड प्लान चौपट: डॉक्टर घूमने नहीं जा पा रहे

साल का आखिरी महीना खत्म होने को है, इसको लेकर कुछ डॉक्टर के साथ सीनियर डॉक्टर और स्टाफ ने अपनी छुट्टी बची होने पर घूमने का प्लान काफी पहले से ही बना रखा है। लेकिन हड़ताल के चलते अब डॉक्टर जूडा के आने का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि दो तीन दिन में जूडा के आते ही हम लोग घूमने के लिए जाने का प्लान बना रहे हैं।

सिर्फ इमरजेंसी... बाकी ऑपरेशन टले

पिछले चार दिनों से जूडा की हड़ताल के चलते इमरजेंसी के ऑपरेशन तो हो रहे है। लेकिन रुटीन के काफी ऑपरेशन को टाला जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा केस सर्जरी, आर्थो, न्यूरो सर्जरी, ईएनटी, कार्डियोलॉजी आदि के रोके जा रहे हैं।

जूडा की हड़ताल से परेशानी हो रही है

जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के चलते कुछ परेशानी आने लगी है। वहीं इसको देखते हुए डॉक्टर की ड्यूटी रद्द की गई है। वहीं सीनियर डॉक्टर और अन्य स्टाफ मिलकर व्यवस्था को संभाले हुए हैं।

डॉ. संजय धवले
प्रभारी अधीक्षक जेएएच

हम नहीं सुधरने वाले...

कोविड के नए वैरियंट ओमिक्रोन के लगातार देशभर में मरीज सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद भी शहर में लोग इस तरह बाजारों में भीड़ बढ़ा रहे हैं और तो और इन्हें न तो अपनी चिंता और न अपने परिवार की फिकर। न तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही मास्क लगा रहें है। चित्र महाराज बाड़ा स्थित नजरबाग मार्केट का।

प्रो. संगीता शुक्ला बनीं मेरठ विवि की कुलपति

ग्वालियर @ पत्रिका. प्रोफेसर संगीता शुक्ला को मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। उत्तरप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका नियुक्ति आदेश गुरुवार को जारी किया। वे ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान विषय की प्राध्यापक हैं। वे यहां कुलपति भी रही हैं। जीवाजी विवि में वे दो बार कुलपति भी रही हैं। उनका कुलपति के रूप में दूसरा कार्यकाल 18 नवंबर को समाप्त हुआ था। हालांकि वे नए कुलपति की नियुक्ति तक यह दायित्व संभाले रहीं।

खुलासा

रायसेन जिले में विधायक निधि और सांसद स्वेच्छानुदान में हुआ था 97 लाख का गबन

गबन मामले के बाद कैग की सरकार को सलाह, सिस्टम का कराए सुरक्षा ऑडिट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

ग्वालियर. रायसेन जिले में योजना एवं सांख्यिकी विभाग के दस्तावेज की जांच में बड़ी आर्थिक अनियमितता सामने आई। यहां विधायक निधि और सांसद स्वेच्छानुदान की राशि में गड़बड़ी की गई। कैग के अनुसार यहां 97 लाख से अधिक का गबन हुआ था। इस आधार पर कैग ने सरकार को अपने सिस्टम का निश्चित समय अंतराल में सुरक्षा ऑडिट कराने की सलाह दी है। कैग की सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र की रिपोर्ट में इसकी अनुशंसा करते हुए सरकारी योजना के हितग्राहियों के आवश्यक विवरण आधार से लिंक कर बैंक खातों से अभिप्रमाणित करने को कहा गया है। साथ ही केवल अधिकृत व्यक्तियों की ही इस प्रणाली तक पहुंच हो। धोखाधड़ी और आर्थिक अनियमितता रोकने के लिए सुरक्षा उपायों जैसे लेनदेन संबंधी सावधानी, पासवर्ड की गोपनीयता के संबंध में स्टाफ को जागरुक किया जाए।

इस तरह की गड़बड़ी

डाटा एंट्री ऑपरेटर ने अपने व्यक्तिगत खाते, पत्नी

और भाई समेत अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों, संस्थाओं, एनजीओ के बैंक खातों से हितग्राहियों के नाम जोड़कर बड़ा हेरफेर कर दिया। इसमें 97 लाख 6 हजार रुपए का गबन सामने आया। इसके खिलाफ इसी साल जनवरी में एफआईआर कराई गई।

पासवर्ड की गोपनीयता नहीं रखी इसलिए हुआ था गबन

कैग की रिपोर्ट में इस गबन का उल्लेख है। रायसेन जिले में जनवरी से अगस्त 2019 के इन दस्तावेज के ऑडिट में मालूम चला कि विधायक निधि योजना एवं सांसद स्वेच्छानुदान के हितग्राहियों को भुगतान की गई राशि का मिलान नहीं हो रहा। कैश बुक और बिल रजिस्टर की प्रविष्टियां कोषालय की वाउचर स्लिप से अलग थीं। इसकी वजह आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा देयकों का हितग्राहियों के बैंक खातों से सत्यापन नहीं किया गया। यही नहीं अधिकारी ने अपने लॉगइन-पासवर्ड की गोपनीयता भी नहीं रखी। इसको डाटा एंट्री ऑपरेटर को बता दिया गया। जबकि वह संविदा कर्मचारी था। यही वजह रही कि उसने इसका दुरुपयोग किया।

दैनिक भास्कर, ग्वालियर संस्करण, दि. 24.12.2021

कैग की रिपोर्ट • 2014 से 2019 तक खाद्य विभाग के अमले ने त्योहारों पर की खानापूर्ति

मिलावट रोकने 5 साल में सिर्फ 241 सैंपल

सिटी रिपोर्टर | ग्वालियर

खाद्य विभाग का अमला होली, दशहरा और दीपावली के त्योहारी सीजन में भी सैंपलिंग तक ज्यादा नहीं करता। इसका खुलासा हुआ है कैग रिपोर्ट से। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 से 2019 तक तीन बड़े त्योहारों पर खाद्य विभाग सिर्फ 241 सैंपल ही बाजार से ले सका। जबकि, इन सीजन ही मिलावटी एवं नकली खाद्य पदार्थों को सबसे ज्यादा खपाया जाता है।

तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने 2019 में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया था। जिसके तहत मिलावट खोरों के खिलाफ बड़े स्तर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान त्योहारी सीजन में 5 साल के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा 66 सैंपल लिए गए। अधिकारियों के अनुसार ये आंकड़ा भी अपेक्षित कार्रवाई की तुलना में काफी कम था। क्योंकि, मिलावट एवं नकली खाद्य पदार्थों को लेकर ग्वालियर, मुरैना और भिंड से ही सबसे ज्यादा शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय के पास गई थीं।

गौरतलब है कि ग्वालियर नकली घी को लेकर बड़े माफिया सेंटर के तौर पर उस वक्त एक्सपोज हुआ था। जब शिर्डी साईं बाबा मंदिर के प्रसाद में उपयोग किया जा रहा घी नकली निकला। ये घी ट्रांसपोर्ट नगर की एक फैक्ट्री से तैयार कर भेजा गया था। ऐसे ही तिरूपति मंदिर में भी नकली घी मिला और उसकी सप्लाई भी ग्वालियर से हुई थी। जिसके बाद ग्वालियर में छापेमार कार्रवाई हुई व ऐसे कई लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। जो कि नकली घी बनाने व सप्लाई करने का काम कर रहे थे।

दशहरा दीपावली और होली पर किस साल कितने सैंपल लिए

वर्ष	सैंपल संख्या
2014-2015	42
2015-2016	53
2016-2017	25
2017-2018	55
2018-2019	66

स्टाफ के लिए प्रस्ताव भेजा

ग्वालियर| जिला अस्पताल के जच्चाखाने में पीडियाट्रिक आईसीयू अभी हैडओवर नहीं हुआ है। पीआईसीयू को शुरू करने के लिए सिविल सर्जन डॉ. आरके. शर्मा ने 4 डॉक्टर, 6 नर्सिंग स्टाफ, 6 वार्ड ब्वॉय, 4 स्वीपर और 4 सुरक्षाकर्मियों की मांग का प्रस्ताव शासन को भेजा है।

बंद हो सकती है थैरेपी

ग्वालियर| जयारोग्य चिकित्सालय के ऑकोलॉजी विभाग में जल्द ही टेक्नीशियन की भर्ती नहीं की गई तो एआरबी कोबाल्ट थैरेपी के संचालन का लाइसेंस रद्द कर सकती है। विभागाध्यक्ष डॉ. अक्षय निगम ने बताया कि एआरबी के नियमानुसार कम से कम दो टेक्नीशियन होना चाहिए। इसके लिए नोटिस भेजा है।

बिना स्वीकृति के कॉलोनी बस रही थी, निगम अमले ने तुड़ाई की

ग्वालियर| नए आरटीओ ऑफिस के पास नीलामी में जिला प्रशासन से खरीदी जमीन पर बिना रजिस्ट्री, बिना नगर निगम परमिशन के अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर गुरुवार को निगम ने कार्रवाई की। नीलामी में जमीन लेने वाले आकाश शर्मा और संजय दीक्षित विरोध करने आ गए। भवन अधिकारी बीके त्यागी ने रजिस्ट्री, टीएंडसीपी और निगम से परमिशन मांगी। उनके पास ऐसे कुछ कागजात नहीं मिले। इसके बाद कॉलोनी में डाली गई सीवर लाइन, सड़क आदि को तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन से 7.5 बीघा जमीन नीलामी में इन लोगों ने खरीदी थी। यहां कॉलोनी बसाने से पहले परमिशन लेना थी, लेकिन नहीं ली गई।

तीन पूर्व सरपंचों ने किया शासकीय धन का दुरुपयोग, जेल भेजे जाएंगे

ग्वालियर| शासकीय धनराशि निकालने के बाद उसका निर्माण कार्य पूर्ण कराने में उपयोग न कर शासकीय धन का दुरूपयोग करने वाले पूर्व सरपंच सिसगांव के राजेंद्र सिंह परिहार, उटीला से नारायण सिंह जाटव और नौगांव से रामलखन सिंह गुर्जर जेल जाएंगे। जिला पंचायत के सीईओ आशीष तिवारी ने पंचायत राज अधिनियम की धारा-92 के तहत इस आशय के अलग-अलग आदेश जारी कर इन पूर्व सरपंचों को अभिरक्षा में लेकर 30 दिवस के लिए जेल में रखने के निर्देश केंद्रीय जेल, अधीक्षक को दिए हैं।

डॉक्टर ने नौगांव में खरीदी जमीन, अब बेचने वाले का बेटा मांग रहा पैसे, एफआईआर

ग्वालियर| जयारोग्य अस्पताल के डॉ. धुंआराम सिंह ने नौगांव में भगवान सिंह व उसके परिवार से जमीन खरीदी थी। जमीन में जिन लोगों का हिस्सा था, सभी को रुपए दिए। इसके बाद नामांतरण कराया फिर बाउंड्री कराई। अब भगवान सिंह के परिवार का मुकेश बघेल डॉक्टर से और पैसे मांग रहा है। डॉक्टर के शिकायती आवेदन की जांच के बाद एफआईआर दर्ज की। उधर, गेंडेवाली सड़क पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में इंदरगंज पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर नेहरू वाल्मीक पर एफआईआर दर्ज की है।

भाजपा को समझने किसी किताब की जरूरत नहीं, अभ्यास वर्ग से विचारों को समझ सकते हैं: तोमर

ग्वालियर| केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा को समझने और पार्टी के विचारों को आत्मसात करने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं होती है, बल्कि अभ्यास वर्ग इसका जरिया है। वे झांसी रोड पर आयोजित भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सांसद विवेक शेजवलकर, जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी उपस्थित थे। पूर्वमंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि भारतीय सैन्य शक्ति का मनोबल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में आसमान छू रहा है। आज भारत 101 देशी शस्त्रों का निर्माण कर रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री तोमर 25 व 26 दिसंबर को ग्वालियर व मुरैना के दौरे पर रहेंगे।

Scanned by CamScanner

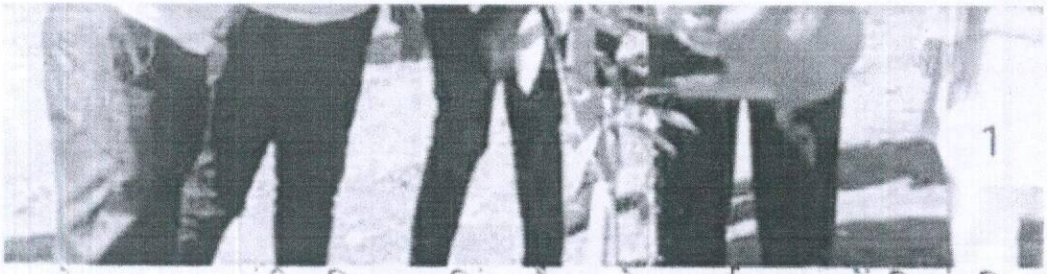

भोपाल- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट उद्यान में दिशांजलि ए सोसायटी के प्रतिनिधियों के साथ सप्तपर्णी और कदंब का पौधा लगाया। मुख्य सोसायटी के अंकित सिंह, सुश्री सौम्या गोयल, विकास सक्सेना और अजय व रोपण किया।

समाचार सं

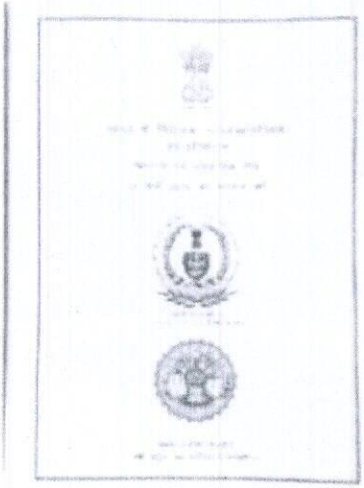

घोटालों, अनियमितताओं, नियम विरोधी कार्यों के सरकारी सबूत ; फिर भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं हैं सरकारें

(पेज 4 पर)

मुख्यमंत्री शिवराज के खिलाफ मुकदमें के लिए सांसद तन्खा ने डेढ़ लाख रूपये न्यायालय में जमा कराए

भोपाल, 24 दिसम्बर(ए.)। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ओबीसी आरक्षण मामले में आरोप लगाए जाने पर सख्त एक्शन लिया है। तीन दिन में माफी मांगने की मोहलत समाप्त होने के बाद उन्होंने अब कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह पर 10 करोड़ रुपए मानहानि का दावा करते हुए इसके लिए जरूरी डेढ़ लाख रुपए का चेक जमा करा (शेष पेज 11 पर)

अ

बच्

ग्वालि
आरएस
विद्याभा
प्रांतीय
राजेश
कि सर
में मुस्
मुस्लिम
ग्वालि
उन्होंने
शुक्ला
वजह है
मंदिर स
यहां

ग्वालियर हलचल
सान्ध्य दैनिक

ग्वालियर हलचल सान्ध्य दै
www. gwaliorhulcha... प

भाजपा पिछडा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी ...पार्

पेज - 4

सम्पादकीय

ग्वालियर, शुक्रवार, 24 दिसम्बर 2021

घोटालों, अनियमितताओं , नियम विरोधी कार्यों के सरकारी सबूत ; फिर भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं हैं सरकारें

इसे भारतीय संविधान की बहुत बड़ी प्रशासनिक और कानूनी कमी कही जा सकती है कि सरकारी विभागों में घोटालों , अनियमितताओं, नियम विरोधी कामों का ऑडिट करने वाले भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सीएजी) की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं।

यही वजह है कि हर वर्ष महालेखापरीक्षक(एकाउंटेण्ट जनरल)कार्यालयों की ऑडिट रिपोर्ट संसद में, विधानसभाओं में, राज्यों के मुख्य सचिव कार्यालयों में जमा होती हैं फिर धूल खा रही होती हैं।

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के मध्यप्रदेश प्रधान महालेखाकार ने 21 दिसम्बर को मध्यप्रदेश विधानसभा 31 मार्च को सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन सौंपा है। इसके कुछ अंश का जिक्र करते हैं- जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, रायसेन के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विधायक निधि योजना व सांसद स्वेच्छानुदान में अपात्र व्यक्तियों को भुगतान करने से 97 लाख रूपये का गबन हुआ।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के क्रियान्वन में मध्यप्रदेश शासन की प्रशासकीय तंत्र की कमी के कारण 3 करोड़ 64 लाख रूपये की अर्थदण्ड राशि वसूली नहीं जा सकी और दोषी खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरुध्द राजस्व वसूली प्रमाणपत्र की कार्यवाही नहीं हो सकी।

मध्यप्रदेश के खेल विभाग ने 2014 से 19 तक 15 आदिवासी बहुल जिलों में एक भी खेल अकादमी की स्थापना नहीं की , जबकि जनजातीय जनसंख्या में छुपी हुई प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए खेल विभाग ने 36 करोड़ 41 लाख रूपये खर्च किए थे। प्रदेश भर की खेल अकादमियों में प्रशिक्षकों की कमी 65 प्रतिशत तक थी।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उदयगढ़, अलीराजपुर और उप कोषालय जोबट, अलीराजपुर के कर्मचारियों ने 16 करोड़ 43 लाख रूपये कपटपूर्ण तरीके से निकाले।

मध्यप्रदेश शासन ने खाद्य सुरक्षा के लिए पृथक अधिकरणों एवं न्यायालय की स्थापना नहीं की। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने जिलावार अपील प्रकरणों पर जानकारी संधारित नहीं की थी।

उपरोक्त प्रकरणों के साथ दर्जनों प्रकरण इस एजी रिपोर्ट में है, जो प्रमाण सहित दर्शाते हैं कि सरकारी विभागों में अनियमितताएं हैं। जैसे, पेज 26 में उल्लेख है- देशी-विदेशी शराब के विक्रय में लगे 794 खाद्य कारोबार कर्ताओं के पास लायसेंस-पंजीयन नहीं था। 4482 उचित मूल्य की दुकानों के पास लायसेंस-पंजीयन नहीं था।

(भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक गिरीश चन्द्र मुर्मू और प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) मध्यप्रदेश डी.साहू इसी प्रतिवेदन में लिखते हैं कि भविष्य में शासकीय धन के कपटपूर्ण आहरण को रोकने के लिए विभाग को कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है और उत्तरदायी अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर दोषियों को न्यायपालिका के समक्ष लाया जाए।)

हालांकि एक दशक पहले सीएजी की 2जी स्पेक्ट्रम रिपोर्ट ने जरूर संसद में और मीडिया में खूब स्थान पाया, मनमोहन सरकार के खिलाफ माहौल बना। बाद में 2जी स्पेक्ट्रम गड़बड़ी प्रकरण न्यायालय गया और कह सकते हैं कि मनमोहन सरकार की 2004 के आम चुनावों में विदाई में सीएजी रिपोर्ट की भी अहम भूमिका रही थी। वैसे, यह भी सच है कि उस समय खबरों के प्रसारण , प्रकाशन में उदारीकरण था। यानी शीर्ष सत्ता के खिलाफ निष्पक्ष समाचार परोसे जा रहे थे। आज इस तरह की निर्भिक पत्रकारिता का अभाव है।

सीएजी की विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट पर अनिवार्य रूप से कानून सम्मत कार्रवाई हो, इसके लिए सभी दलों को एक मत होकर कानून बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब महालेखाकार कार्यालयों पर अरबों रूपयों का बजट व्यय हो रहा है तो राष्ट्रहित में इसका सदुपयोग तो दिखे।